

28.12.22

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 से 4 के वकील उपस्थित।

प्रार्थना पुत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थिनी (प्रतिवादिनी सं. 4) की बहस है कि विप्रार्थीगण (वादीगण) ने प्रार्थिनी सं. 4 की मौजा भणा मगरा अवस्थित कय शुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 208/1 रकब 87.15 बीघा मे से 43.17 बीघा भूमि में स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 4/9 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद में उक्त भूमि पूनमाराम की पुश्तैनी होना व इस वजह से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना जन्मतः हक होना बताकर पूनमाराम द्वारा प्रार्थिनी को किये गये 43.17 बीघा भूमि के दिनांक 04.07.2006 के बेचान को अपने 1/3 हिस्से की सीमा तक शून्य घोषित करवाने की मांग है। जबकि मूल ग्राम करना की खसरा नम्बर 208 रकबा 363.03 बीघा भूमि की तत्कालीन खातेदार श्रीमति चौथी पत्नि सोनाराम द्वारा उक्त खसरे की 175.10 बीघा भूमि पूनमाराम जोगाराम पि0 राउराम को दिनांक 29.11.71 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर पूनमाराम की कयशुदा एवं स्वार्जित थी। बाद में पूनमाराम ने उक्त कयशुदा भूमि का सक्षम न्यायालय से विभाजन करवाया, जिससे खसरा नम्बर 208/1 रकबा 87.15 बीघा भूमि पूनमाराम की आवंगी खातेदारी में दर्ज हुई। पुनः पूनमाराम ने उक्त भूमि में से 43.17 बीघा अर्थात् 7.0949 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्ट्री प्रार्थिनी को बेचान किया, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार स्वार्जित सम्पति होने से पूनमाराम को पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त उक्त बेचान को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं होकर सिविल न्यायालय में निहित होने से भी प्रस्तुत वाद काबिल खारिज है। अतः वादीगण का वाद विक्रेता की स्वार्जित सम्पति का पूनमाराम द्वारा किये गये बेचान को गलत रूप से पुश्तैनी सम्पति बताकर किया गया होना बताते हुए प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। अपनी दलील के समर्थन में वकील प्रार्थिनी ने RJB 2021 पृष्ठ 233 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया।

इसके विपरित वकील विप्रार्थीगण (वादीगण) की बहस है कि मुतवफी पूनमाराम के अपने पुत्र भंवराराम के साथ निवास होने के कारण भंवराराम ने पूनमाराम पर दबाव बनाकर वादग्रस्त भूमि का अपनी पत्नी प्रार्थिनी के हक में बेचान करवा लिया, जबकि दौराने बेचान वादीगण का जन्म हो चुका होने से जन्मतः उक्त सम्पति में अपने दादा व पिता के साथ हक उत्पन्न हो चुके थे,

28/12/2022
SDO सिविल
सि. नं. 14

86/20 21

क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत दादा की सम्पत्ति में उसके पोते-पोतियों का जन्मतः हक होता है, जिसे घोषित करने एवं अविधिसम्मत बेचान को शून्य करार देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित होता है। वादीगण ने अपने वाद में बेचान को निरस्त करने की नहीं, बल्कि अपने हिस्से की सीमा तक उसे शून्य घोषित करने की इस्तदुआ चाही है, जो निसर्देह राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। प्रतिवादी सं. 2 ने न केवल पूनमाराम के जीवनकाल में अपनी पत्नी के नाम बेचान करवाया, बल्कि पूनमाराम की मृत्यु के बाद शेष भूमि से 1/3 हिस्से की खातेदार बनी अणदूदेवी पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में उसके हिस्से का हकतर्क करवा लिया, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम वादग्रस्त भूमि हड़पने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। अपनी बहस जारी रखते हुए विप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 4 द्वारा वादीगण को उनके जायज पुश्तैनी हकों से महरूम रखने, प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने और वादीगण को अनावश्यक खर्च से परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो सारहीन, विधिविरुद्ध एवं बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थना पत्र का मूल विचारणीय बिन्दु यही है कि पूनमाराम द्वारा प्रतिवादी सं. 4 को किये गये बेचान वाली भूमि में वादीगण के हक निहित है अथवा नहीं। ग्राम करना के ना0क0सं0 149, जो श्रीमति चौथीदेवी द्वारा पूनमाराम व जोगाराम द्वारा जरिये रजिस्ट्री कय की गई खसरा संख्या 208 की 175.10 बीघा भूमि के संबंध में दायर किया गया था, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भूका द्वारा बिना वजह का उल्लेख किये अस्वीकार कर दिया था। बाद में न्यायालय का आदेश पारित होने पर जयि ना.क.सं. 290 मौजा करना कयशुदा 175.10 बीघा भूमि केतागण पूनमाराम व जोगाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर पूनमाराम की कयशुदा एवं स्वार्जित थी, जिसे बेचान, रहन इत्यादि करने का उसे पूर्ण अधिकार था। यद्यपि वादीगण का यह कथन सही है कि पुश्तैनी सम्पत्ति, जो दादा की हो, में पोते-पोतियों का जन्मतः हक होता है, किंतु उनके हक, यदि सम्पत्ति दादा की स्वार्जित हो, दादा के जीवनकाल में उत्पन्न नहीं होते हैं। बह अपने जीवनकाल में स्वार्जित खातेदारी भूमि का किसी भी विधि से हस्तांतरण करने में पूर्ण सक्षम है। प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्प होते हैं। उक्त भूमि में विप्रार्थीगण के हक उसी सूरत में पैदा होते, जबकि पूनमाराम बिना बेचान किये फौत हुआ होता। किंतु चूंकि पूनमाराम प्रार्थनी को वादग्रस्त भूमि का बेचान करने के बाद फौत हुआ है। अतः उक्त बेचानशुदा भूमि में

दी. 14
28/12/2022
उपलब्ध करके
SDO सिणधरी
सिणधरी

विप्रार्थीगण की कोई दावेदारी नहीं बनती है। उक्त विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि पूनमाराम द्वारा अपनी कयशुदा भूमि का प्रार्थिनी को किया गया बेचान पूर्णतः विधिसम्मत है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

28/12/2022
उपस्थित कलेक्टर
SPO सिपधरी
सिपधरी